भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2010

उत्तर देने की तारीख -11.12.2025

जनजातीय आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं की कमी

2010. **एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2025 में पांच राज्यों में जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों के पहले सर्वेक्षण पर ध्यान दिया है, जिसमें बुनियादी ढ़ांचे में महत्वपूर्ण खामियां जैसे कि 40 बच्चों पर केवल एक शौचालय, पुस्तकालयों और खेल सुविधाओं की कमी का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में विशेषकर पिछड़े जनजातीय जिलों में कितने जनजातीय आवासीय विद्यालय इस सर्वेक्षण का हिस्सा थे तथा कितने विद्यालयों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है;

(ग) क्या नंदुरबार जैसे जिलों में जनजातीय आवासीय विद्यालयों में नवीनीकरण, बुनियादी ढ़ांचे के उन्नयन, स्वच्छता, पुस्तकालय, खेल सुविधा में सुधार के लिए विशेष रूप से कोई अतिरिक्त धनराशि या योजना की घोषणा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को कब तक उम्मीद है कि महाराष्ट्र के जनजातीय आवासीय विद्यालयों में सभी बताए गए बुनियादी ढ़ांचे की कमियों को पूरा कर लिया जाएगा और इस बारे में सार्वजनिक प्रगति रिपोर्ट कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क); जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2025 में जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2024 में जनजातीय आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के आंकलन और मूल्यांकन से संबंधित ऐसी दो परियोजनाएं सौंपी है।

(ख): एनएबीईटी द्वारा सौंपी की गई आंकलन रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 35 विद्यालयों और 22 छात्रावासों का आंकलन किया है। महाराष्ट्र में एक अन्य सर्वेक्षण में37 ईएमआरएस का मूल्यांकन भी किया गया है।

(ग) और (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 02 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना शुरू की है, जिसमें 17-संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए 25 उपाय शामिल हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के तहत, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आश्रम स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं, फर्नीचर, बड़े मरम्मत के काम, शौचालय ब्लॉक इत्यादि के निर्माण के लिए परियोजना भेज सकते हैं।

दाजगुआ योजना के अंतर्गत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने नंदुरबार जिले सहित महाराष्ट्र राज्य सरकार को अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालय ब्लॉकों और प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए 999.11 लाख रुपये जारी किए हैं। सभी गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र को जारी की गई कुल धनराशि 22388.08 लाख रुपये है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। दाजगुआ योजना के अंतर्गत पुस्तकालय और खेल सुविधाओं का प्रावधान नहीं है।

*****